हड़कंप

ऑपरेटर और अधिकारी की कथित कारस्तानी से मचा हड़कंप, वीडियो ने खोली 'वसूली सिंडिकेट' की परतें

रिश्वत नहीं दी तो थमा दी गोदाम की झाड़ू!

नवभारत, किरनापुर। किरनापुर महिला एवं बाल विकास परियोजना में सामने आया आंगनवाड़ी भर्ती वसूली कांड अब महज भ्रष्टाचार का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह अफसरशाही के उस तल्ख चेहरे को उजागर कर रहा है जहां जनप्रतिनिधियों की शिकायतें वर्षों तक दफ्तरों की फाइलों में दबी रहीं, लेकिन एक मामूली मानदेय पाने वाली सहायिका ने जब रिश्वत देने से इंकार किया तो उसे गोदाम की साफ.-सफाई कराने तक का फरमान सुना दिया गया। हैरत की बात यह है कि पैसों की मांग करते वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के बावजूद ऑपरेटर पर तो गाज गिरी, जबकि कथित तौर पर पूरे खेल की अहम किरदार मानी जा रही परियोजना अधिकारी अमृता कुजूर पर सिर्फ विभागीय जांच बैठाकर मामला ठंडा करने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। अब इस पूरे मामले यदि वीडियो, दस्तावेज और शिकायतें भी पर्याप्त नहीं मानी जा रहीं, तो फिर न्याय की उम्मीद आखिर किससे की जाए।

उल्लेखनीय है की महिला एवं बाल विकास विभाग की किरनापुर परियोजना इन दिनों भारी सुर्खियों में है। यहां आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती के नाम पर कथित वसूली, दबाव और प्रताडना का ऐसा मामला सामने आया है जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि एक तरफ ऑपरेटर का पैसों की मांग करते वीडियो चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले में बराबर की हिस्सेदार बताई जा रही परियोजना अधिकारी पर सिर्फ विभागीय जांच बैठाकर खानापूर्ति किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

सजा के तौर पर गोदाम की साफ सफाई करने का फरमान

शिकायत के बाद जो हुआ उसने लोगों को और ज्यादा हैरत में डाल दिया। आरोप है कि 27 अप्रैल 2026 को जारी पत्र क्रमांक 204 के जरिए सीमा बिसेन को सप्ताह में तीन दिन कार्यालय के गोदाम की साफ सफाई करने का फरमान सुना दिया गया। एक सहायिका से भृत्य जैसा काम कराए जाने को लेकर अब विभाग कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। क्षेत्र में लोग इसे आवाज उठाने की सजा बता रहे हैं। सूत्रों की मानें तो यह पहला मौका नहीं है जब ऑपरेटर रिजवान अंसारी का नाम विवादों में आया हो। वर्ष 2022 में भी उन पर फर्जी हस्ताक्षर कर

दस्तावेज तैयार करने के आरोप लगे थे। उस दौरान कई सेक्टर प्रभारियों ने कथित दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया था। बावजूद इसके वर्षों तक कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ी रही।

हालांकि मामले के तूल पकडने् के बाद प्रभारी परियोजना अधिकारी जागृति बघेल ने रिजवान अंसारी को प्रभारी जिला परियोजना अधिकारी के आदेश के परिपालन मे उसे पद से पृथक करने का एक पत्र जारी कर दिया है लेकिन मुख्य परियोजना अधिकारी अमृता कुजूर पर केवल विभागीय जांच समिति गठित हुई है या नहीं यह शंसय बना हुआ है जिससे अनेक सवाल उठ खड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि अगर कथित वसूली का खेल चल रहा था तो क्या यह सब बिना वरिष्ठ अधिकारी की मर्जी के संभव था? क्षेत्र में अब यह चर्चा भी आम हो गई है कि कहीं पूरा मामला सिर्फ एक कर्मचारी पर कार्रवाई कर असली जिम्मेदारों को बचाने की कवायद तो नहीं है? वहीं शिकायत करने वाली सहायिकाओं में भी खौफ का माहौल बताया जा रहा है। उन्हें डर है कि आने वाले समय में अफसरशाही कहीं अपनी फजीहत का बदला उनसे न निकाले।

जिला कार्यालय में अब भी कार्य कर रहा ऑपरेटर

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार किरनापुर परियोजना कार्यालय से हटाये जाने के बाद भी कम्प्यूटर ऑपरेटर बालाघाट मुख्यालय में स्थित जिला परियोजना कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा है।

जबकि नियमानुसार जब उक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर को पद से पृथक कर दिया गया है तो वह किस नियम के आधार पर जिला कार्यालय में कार्य कर रहा है यह विभागीय अधिकारी ही बता सकते हैं।

नव नियुक्त सहायिकाओं से 13-13 हजार रुपये की मांग

मामला सितंबर 2025 में हुई आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती से जुड़ा बताया जा रहा है। किरनापुर परियोजना अंतर्गत 19 ग्रामों में सहायिकाओं की नियुक्तियां मेरिट सूची के आधार पर की गई थीं। आरोप है कि नियुक्ति के बाद परियोजना कार्यालय में पदस्थ ऑपरेटर रिजवान अंसारी और परियोजना अधिकारी अमृता कुजूर ने नव नियुक्त सहायिकाओं से 13-13 हजार रुपये की मांग शुरू कर दी। कहा गया कि रकम देने पर नियुक्ति संबंधी कार्य आसानी से होंगे और आगे किसी जांच या कार्रवाई में ढील भी मिलती रहेगी। पूरा मामला तब बेनकाब हुआ जब बटामा आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक -1 की सहायिका सीमा बिसेन ने रुपये देने से इंकार कर दिया। बताया जाता है कि सीमा ने हिम्मत दिखाते हुए कथित वसूली से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्य जुटाकर जनसुनवाई में शिकायत दर्ज करा दी। वायरल वीडियो में ऑपरेटर कथित तौर पर खुलेआम पैसों की मांग करता दिखाई दे रहा है, जिसने विभाग में खलबली मचा दी है।

इनका कहना है....

कार्यालय में भृत्य होने के बावजूद बटामा आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 की सहायिका को गोदाम की सफाई व्यवस्था के लिये पत्र जारी करना पूरी तरह गलत है। इस संबंध में जिन्होने पत्र जारी किया है उन्हें इसके लिये नोटिस जारी होना चाहिए और जवाब तलब करना चाहिए। साथ ही कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरूद्ध जनसुनवाई में शिकायत पहुंच चुकी है जिसके बाद उसे पद से हटा दिया गया है।

दीपमाला सोलंकी
जिला परियोजना अधिकारी बालाघाट

इस मामले की जानकारी या शिकायत अभी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। जनसुनवाई में अगर इस मामले को लेकर शिकायत हुई है तो हमारे पास जरूर आएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आदित्य नारायण तिवारी
एसडीएम, किरनापुर

निष्कासन सिर्फ दिखावा, विधायक प्रतिनिधियों की वापसी से फिर गरमाई राजनीति

नवभारत, बालाघाट। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनुभद्य मुंजारे एक बार फिर अपने विधायक प्रतिनिधियों को लेकर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। जिन विधायक प्रतिनिधियों को पहले सार्वजनिक विवादों और शिकायतों के बाद हटाए जाने की घोषणा की गई थी, वही चेहरे अब फिर विधायक के सरकारी निवास पर सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

जानकारी के अनुसार विधायक प्रतिनिधि अब्बू शाह पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बदसलूकी और मोबाइल पर धमकी देने के आरोप लगे थे। मामला सार्वजनिक होने के बाद विधायक द्वारा उन्हें प्रतिनिधि पद से हटाने की बात कही गई थी। वहीं दूसरे प्रतिनिधि निराला पर लालबर्रा क्षेत्र में बन रही सड़क निर्माण में कमीशन मांगने के आरोप लगे थे। उस समय विपक्ष

सहित स्थानीय लोगों ने भी इस मामले को जोर-शोर से उठाया था।

लेकिन अब क्षेत्र में चर्चा है कि दोनों ही पूर्व विधायक प्रतिनिधि आज भी विधायक के सरकारी निवास पर पूरे प्रभाव के साथ सक्रिय हैं। सूत्रों का कहना है कि दिनभर अधिकारियों को फोन लगाना, विभागीय कार्यों में हस्तक्षेप करना और पुराने तरीके से काम करवाना लगातार जारी है। इससे यह सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर निष्कासन वास्तविक था या केवल जनता के गुस्से को शांत करने के लिए किया गया कदम।

सबसे ज्यादा चर्चा अब्बू शाह को विधायक निधि से लगभग 90 लाख रुपए के ठेके दिए जाने को लेकर हो रही है। आमजन यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को विवादों और शिकायतों के कारण पद से हटाया गया था, तो फिर उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी और आर्थिक लाभ कैसे दिया गया।

क्षेत्र में यह चर्चा भी तेजी से फैल रही है कि विधायक अनुभद्य मुंजारे सार्वजनिक मंचों पर पारदर्शिता और अनुशासन की बात करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वही विवादित चेहरे उनके सबसे करीबी माने जा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी कई वरिष्ठ कार्यकर्ता इस स्थिति से नाराज बताए जा रहे हैं।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लगातार सामने आ रहे ऐसे विवादों से विधायक की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं आम जनता के बीच एक ही चर्चा सुनाई दे रही है — 'विधायक जी कहती कुछ हैं और करती कुछ हैं।'

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

बालाघाट। प्रदेश में शासकीय कार्यप्रणाली में नवाचार, सुशासन और जनसेवा के उत्कृष्ट प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 'मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार' (नवाचार हेतु) वर्ष 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने जानकारी दी कि यह पुरस्कार मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा उनके अधीन कार्यरत निगम, मंडल, बोर्ड एवं संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारियों को उनके नवाचार आधारित उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा।

यह पुरस्कार 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिये प्रदान किये जायेंगे। ऐसे कार्य जिनसे प्रशासनिक कार्यप्रणाली, सेवा प्रदाय व्यवस्था अथवा जनहित में सकारात्मक और प्रभावी परिवर्तन आया हो।

सोमवार से शनिवार तक खुले रहेंगे खरीदी केंद्र

बालाघाट। प्रदेश शासन ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए अब शनिवार को भी समर्थन मूल्य पर चना एवं सरसों की खरीदी करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अब तक समर्थन मूल्य पर चना एवं सरसों खरीदी योजना अंतर्गत खरीदी केंद्रों पर सप्ताह में केवल पांच दिन, सोमवार से शुक्रवार तक ही खरीदी की जाती थी।

बालाघाट-बोनकट्टा-तिरोड़ी थाना का लिस्टेड गुंडा गुरुदेव पुस्पतोड़े उर्फ गुरु अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर

नवभारत, बालाघाट। बालाघाट-बोनकट्टा-तिरोड़ी थाना का लिस्टेड गुंडा गुरुदेव पुस्पतोड़े उर्फ गुरु अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर । खबर ये भी है की गुरु अभी महाराष्ट्रा के किस नेता के घर में छुपा है जिसके अपराध की कुंडली बहुत बड़ी है उसके कुछ अंश की सूची इस प्रकार है 1- आरटीओ विभाग में अधिकारी रहंगड़ाले के ऊपर किया था प्राणघातक हमला जिसमे जेल भी गया था । 2 - इसके पूर्व में भी बम्हनी (बावनथेडी) नदी में रेत के अवैध उत्खनन के ख़िलाफ़ कार्यवाही करने गए राजस्व अधिकारी तहसीलदार / पटवारी के ऊपर हमला किया जिसमे भी जेल गया महिला अधिकारी से भी मारपीट का आरोप । 3- जनपद अध्यक्ष के घर ?? में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था । 4- शादी का झाँसा देकर महिला से बलात्कार और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का केस अभी भी चल रहा है । 5- अभी हाल में ही रेत चोरी की स्न्ढ्ढक्रजिसमे अभी तक फरार है ! 6- उगली थाने में भी मारपीट गुंडागर्दी की स्न्ढ्ढक्रदर्ज है । 7- बालाघाट-महाराष्ट्र बॉर्डर से सटे बोनकट्टा तिरोड़ी थाना गोबरवाही महाराष्ट्र थाने में भी कई अपराध दर्ज हैं ।

पुलिस और राजस्व विभाग को कहीं पूर्व की घटनाओं से भय का माहौल तो नहीं है की उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हो सकता है कहीं इस डर से तो पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और राजस्व विभाग उत्खनन की नपाई करके केस नहीं बना पा रही है ? पूर्व में भी समाचार पत्रों के माध्यम से खबर छपी थी कि गुरदेव उर्फ़ गुरु के द्वारा बोनकट्टा , बांभनी , चाकाहेटी से लगातार 20/25 डम्फ़र प्रतिदिन रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था जिससे राजस्व को करोड़ों की हानि हुई है लेकिन आज तक किसी राजस्व या माइनिंग अधिकारी के द्वारा मौके स्थल में जाकर अवैध रेत उत्खखनन किए गए गड्ढों को नापकर गुरुदेव पुष्पतोड़े के ऊपर कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है क्या ये माफिया इतना पावरफुल है ?

वनरक्षक ने ही कटवा दिए 6 बेशकीमती सागौन के पेड़

- चौकीदारों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में बेची लकड़ी, कटंगी रेंज के आम्बेझरी बीट का मामला, डिप्टी रेंजर की जांच में खुलासा

नवभारत, कटंगी 14 मई। बालाघाट जिले के दक्षिण वन मंडल सामान्य के कटंगी रेंज अंतर्गत कन्हडगांव सर्कल के आम्बेझरी बीट में 'जब रक्षक ही भक्षक बन जाए' वाली कहावत चरितार्थ हुई है। बीट में पदस्थ वनरक्षक संतोष चौबे ने अपने ही दो वन चौकीदारों के साथ मिलकर 6 बेशकीमती सागौन के पेड़ कटवा दिए और लकड़ी महाराष्ट्र में बेच दी।

जानकारी के अनुसार, वनरक्षक संतोष चौबे ने आम्बेझरी निवासी वन चौकीदार रतन और आकाश

के साथ मिलकर आम्बेझरी कक्ष क्रमांक 570 में सागौन के 6 पेड़ कटवा दिए। कटाई के बाद सुनील गौपाले निवासी आम्बेझरी के ट्रैक्टर से 9 मई को सागौन के 7 नग लठ्ठे और 10 मई को 12 नग सागौन की लकड़ियां मध्यप्रदेश की सीमा से लगे महाराष्ट्र प्रांत के ग्राम लोभी में बेच दीं। सबूत मिटाने के लिए पेड़ों के ठूंठों पर आग भी लगा दी गई।

डिप्टी रेंजर की जांच में खुला राज

बीट गार्ड द्वारा जंगल से पेड़ों की कटाई की सूचना मिलते ही डिप्टी रेंजर ओमप्रकाश जगने ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि सागौन के पेड़ों की कटाई की गई है और ट्रैक्टर से लकड़ियों का परिवहन किया गया है। मौका स्थल पर मिले 6 नग सागौन की लकड़ियां जब्त की गईं। जांच में उसी बीट में पदस्थ वनरक्षक चौबे और दोनों चौकीदार दोषी पाए गए।

पहले भी उठ चुका है मामला

डिप्टी रेंजर ने प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही के लिए वन विभाग के कटंगी रेंज अधिकारी को सौंप दिया है। विदित हो कि पूर्व में नवभारत द्वारा बोनकट्टा, गोरेघाट और कन्हडगांव वन क्षेत्रों में हो रही सागौन की अवैध कटाई के समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किए गए थे। वन विभाग की साख पर बट्टा लगाने वाली इस घटना के बाद विभाग में हड़कंप है। अब देखना है कि दोषियों पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है।

इनका कहना है

दोषी कर्मचारियों पर प्रकरण दर्ज कर सस्पेंड करने की कार्यवाही की जा रही है।

बाबूलाल चडार, वन परिक्षेत्र अधिकारी कटंगी

महकेपार सहकारी समिति घोटाले में कार्रवाई के आदेश

- उपायुक्त सहकारिता ने 15 दिन में 2018-19 से 2025-26 तक के धान खरीदी घाटे की राशि वसूलने के दिए निर्देश

नवभारत, कटंगी 14 मई। सेवा सहकारी समिति मर्या महकेपार में हुए धान खरीदी घोटाले में शिकायतकर्ता संदीप सोनवाने की शिकायत पर उपायुक्त सहकारिता जिला बालाघाट ने कड़ा रुख अपनाया है।

उपायुक्त द्वारा 28 अप्रैल को जारी आदेश में 2018-19 से 2025-26 तक के खरीदी कार्य में हुए घाटे

की राशि 15 दिन में वसूल कर समिति के बचत खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं तथा जमा राशि की चालान की प्रति इस कार्यालय में अनिवार्यत: प्रस्तुत करे।

नियुक्तियों पर स्पष्टीकरण तलब

वर्ष 2017-18 से वर्तमान तक समिति में की गई नियुक्तियों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण मय दस्तावेज के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

बिना अनुमोदन के रखे गए कर्मचारी

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय या जिला मुख्यालय कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला बालाघाट से किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है और न ही दैनिक वेतन पर रखने हेतु युक्तियुक्त कार्यवाही पाई गई। तालिका के क्रमांक 02 में उल्लिखित कर्मचारियों की नियुक्ति नियम अनुसार नहीं पाई गई।

धान खरीदी में गबन का हुआ था खुलासा

इससे पहले भी जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट में सेवा सहकारी समिति महकेपार में 2019-20 से 2024-25 तक धान खरीदी में 38,41,807 रुपये के गबन का खुलासा हुआ था। लिपिक रमेश नगपुरे, दीलीप कोठेकार और गोविन्द कुमार आमाडारे को दोषी पाया गया था। रमेश नगपुरे पर 2010 में भी 5,21,580 रुपये के गबन का आरोप था। अब देखना है कि 15 दिन की समयसीमा में वसूली हो पाती है या नहीं, और अवैध नियुक्तियों पर क्या कार्रवाई होती है।

जनता की 7 अपीलों को लेकर पूर्व प्रदेश सचिव जुगल शर्मा ने सरकार से की सादगी अपनाने की मांग

नवभारत, बालाघाट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव जुगल शर्मा ने देश और प्रदेश की वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार से सादगी अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव का सामना कर रही है, तब सरकार और जनप्रतिनिधियों को भी फिजूलखर्ची पर रोक लगाकर जनता के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

जुगल शर्मा ने 'जनता की भी

सरकार से 7 अपील' के माध्यम से सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि एक वर्ष तक सरकारी उत्सवों और अनावश्यक आयोजनों पर रोक लगाई जाए तथा सरकारी कार्यक्रमों में सादगी अपनाई जाए। इसके साथ ही सांसदों और विधायकों के वेतन, भत्तों एवं पेंशन में अस्थायी कटौती कर उस राशि को जनहित और विकास कार्यों में लगाया जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रैलियों में होने वाली भीड़-भाड़ और अनावश्यक खर्च कम होना चाहिए तथा डिजिटल रैली और ऑनलाइन संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विदेशी दौरों, बड़े-बड़े डेलिगेशन और ङ्कढ्ढक्क काफिलों पर होने वाले खर्चों पर भी नियंत्रण जरूरी है।

एक व्यक्ति-चार पद! बालाघाट कांग्रेस में बढ़ता असंतोष, संगठन पर उठे सवाल

नवभारत, बालाघाट। जिला कांग्रेस संगठन में इन दिनों पदों के केंद्रीकरण को लेकर असंतोष लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि संगठन में कुछ चुनिंदा लोगों को लगातार कई-कई जिम्मेदारियां देकर जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है।

सबसे अधिक चर्चा कांग्रेस नेता शफकत खान को लेकर हो रही है, जिनके पास वर्तमान में एक-दो नहीं बल्कि चार-चार महत्वपूर्ण पद बताए जा रहे हैं। इनमें — जिला कांग्रेस कमेटी संगठन महासचिव, निर्वाचन शाखा प्रकोष्ठ प्रभारी, विधायक प्रतिनिधि, नगरीय निकाय प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, जैसी अहम जिम्मेदारियां शामिल हैं।

कार्यकर्ताओं का आरोप है कि क्या संगठन में योग्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं की इतनी कमी हो

गई है कि एक ही व्यक्ति को लगातार कई पद सौंपे जा रहे हैं? उनका कहना है कि इससे वर्षों से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है और संगठन के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है।

कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी हमेशा सामूहिक नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की भागीदारी के सिद्धांत पर आगे बढ़ी है, लेकिन बालाघाट में स्थिति इसके विपरीत नजर आ रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि संगठन कुछ सीमित लोगों के इर्द-गिर्द सिमटता जा रहा है और अधिकांश फैसले भी सीमित दायरे में लिए जा रहे हैं।

राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी खुलकर उठने लगा है कि क्या जिला कांग्रेस संगठन में अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं बचा है? यदि एक ही व्यक्ति को लगातार कई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, तो नए और सक्रिय कार्यकर्ताओं को अवसर कैसे मिलेगा?

कुछ कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय उइके स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेते और अधिकांश फैसले विधायक के इशारे पर किए जाते हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि विधायक स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दूरी बनाकर अपनी अलग टीम तैयार करने में लगी हुई हैं।

कार्यकर्ताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि यदि पिछले 10-15 वर्षों के संगठनात्मक योगदान को देखा जाए, तो शफकत खान की सक्रिय उपस्थिति संगठन के अधिकांश कार्यक्रमों में दिखाई नहीं देती। बावजूद इसके उन्हें लगातार महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी दी जा रही है।

इसके साथ ही कुछ कांग्रेसियों ने वर्ष 2009 के नगरीय निकाय चुनाव का भी उल्लेख करते हुए आरोप लगाया है कि शफकत खान ने वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया था। ऐसे में अब उन्हें संगठन में लगातार अहम पद दिए जाने पर कई कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे हैं। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व से मांग की है कि संगठनात्मक ढांचे की निष्पक्ष समीक्षा कर पदों का संतुलित वितरण किया जाए, ताकि पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान और जिम्मेदारी मिल सके। उनका कहना है कि यदि समय रहते स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो आने वाले चुनावों में इसका नकारात्मक असर कांग्रेस संगठन पर पड़ सकता है।

पीजी कॉलेज बालाघाट में 'भूमि प्लस टी-4' मृदा सुधारक का शुभारंभ

नवभारत, बालाघाट। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक?सीलेंस शासकीय जे.एस.टी.पी.जी. कॉलेज के आईक्यूएसी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में 'भूमि प्लस टी-4' मृदा सुधारक का सफल शुभारंभ किया गया। यह नवाचारपूर्ण उत्पाद सीके लाक इंडस्ट्री एवं महाविद्यालय के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है। इस उत्पाद को दुर्गेश अगासे एवं उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया। टीम में सृष्टि तुरकर, हर्ष हितेंद्र तिवारी, माधवी बिसेन एवं शीफा खान शामिल रहे, जिन्होंने अनुसंधान, विकास एवं प्रस्तुतीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डी.के. राणा रहे। उन्होंने कृषि क्षेत्र में मृदा स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक कृषि में इस प्रकार के नवाचार किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। विशिष्ट

अतिथि एवं अतिथि व्याख्याता उत्तम बिसेन ने कृषि नवाचार, मृदा प्रबंधन एवं वैज्ञानिक तकनीकों के महत्व पर अपने विचार साझा किए।महाविद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार मराठे ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत औद्योगिक संस्थानों की भागीदारी एवं रोजगार के अवसरों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सीमा श्रीवास्तव, पी.एस. कातुलकर, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, एम.एस. मरकाम, प्रवीण कौशले, तारा सिंगराम एवं अनिल झरबड़े ने भी सहभागिता कर अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर तीन महत्वपूर्ण पुस्तकों जैव सांख्यिकी, जैव सूचना विज्ञान एवं संगणकीय जीवविज्ञान, प्रायोगिक मार्गदर्शिका सहित मृदा विज्ञान का परिचय का विमोचन भी किया गया। इन पुस्तकों के लेखक दुर्गेश अगासे, तनुश्री अगासे, हर्ष तिवारी, मुस्कान वैद्य, अमन राहंगडाले, सृष्टि तुरकर, शीफा खान एवं माधवी बिसेन रहे। प्रवीण पारधी ने 'भूमि प्लस टी-4' की विशेषताओं एवं किसानों को होने वाले लाभों की जानकारी देते हुए बताया कि यह उत्पाद मृदा की गुणवत्ता सुधारने, जड़ों के विकास को बढ़ावा देने एवं कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है।

कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान कुँवर बिसेन, विशाल कटरे, सुनील दत्त खरगाल एवं भीकम चंद चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। किसानों ने कृषि नवाचार, मृदा संरक्षण एवं जैविक उर्वरकों के उपयोग पर अपने अनुभव साझा किए।

इस अवसर पर एमपी सेट में चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया, जिससे विद्यार्थियों में उत्साह एवं प्रेरणा का संचार हुआ। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यह आयोजन शिक्षा, अनुसंधान एवं उद्योग के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा, जिसने क्षेत्रीय कृषि विकास एवं किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल प्रस्तुत की।